सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 13 फाल्गुन, 1943 (श०) / 04 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1)	स्वास्थ्य विभाग	05
(2)	ऊर्जा विभाग	02
(3)	योजना एवं विकास विभाग	02
(4)	आपदा प्रबंधन विभाग	01
	कुल योग --	10

औचित्य बतलाना

21. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 26 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार का स्थान छठा, एम0पी0 टॉप पर'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट-2 के ग्रुप बी में शामिल 8 राज्यों में बिहार 6वें स्थान पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ, कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री में 8 में से 7वें स्थान पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 50 प्रतिशत से अधिक डॉक्टर के पद खाली हैं तथा इम्यूनाइजेशन में भी 15.22 प्रतिशत पॉइंट की गिरावट राज्य में दर्ज की गई हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार की उपरोक्त सभी योजनाओं में विफलता का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) Good Governance Index 2021-21 के प्रतिवेदन में ग्रुप बी में राज्यों में 8 राज्यों में बिहार 6वें स्थान पर है ।

(2) गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर का ग्रोथ रेट वर्ष 2019-20 में 2.3 प्रतिशत था, जो 2020-21 में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया न कि निगेटिव ग्रोथ हुआ है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन का वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया है ।

कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री में 8 राज्यों में बिहार 7वें स्थान पर है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के कार्यान्वयन से बिहार में 38 हजार करोड़ रुपयों का निवेश संभावित है । बिहार इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है । इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 4 इथेनॉल इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा 17 इकाइयों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है ।

National Family Health Survey (NFHS)-4 (2015) की तुलना में NFHS-5 (2019-20) में नियमित टीकाकरण के तहत पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन 61.7 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। चिकित्सकों के लगभग 49 प्रतिशत पद रिक्त है, जिनपर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) राज्य सरकार की विफलता का प्रश्न नहीं उठता है । Good Governance Index 2020-21 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार का Overall Score 2019 के 4.40 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4. 62 हो गया है । अर्थात् वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 5 प्रतिशत की प्रगति हुई है । प्रगति के हिसाब से बिहार तीसरे स्थान पर है ।

बिहार में तीन क्षेत्रों, यथा "Public Infrastructure & Utilities", "Social Welfare & Development" तथा "Judiciary & Public Safety" में प्रगति हुई है ।

इसके अतिरिक्त पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड यूटीलीटीज सेक्टर बिहार समूह बी में शीर्ष स्थान पर है । इस सेक्टर के दो सूचकांकों 'Connectivity to Rural Habitation' तथा 'Energy Availability against requirement' में बिहार का प्रतिशत Value क्रमशः 99.9 प्रतिशत तथा 99.7 है ।

बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2005-06 में (-)1.69 प्रतिशत थी, जो अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रतीक रहा है । वर्ष 2006-07 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (स्थिर मूल्य पर) 16.18 प्रतिशत हो गयी । वर्ष 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2018-19, 2019-20 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा रही है । वर्ष 2019-20 में भी राज्य की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है । कोविड 19 के द्वारा उत्पन्न त्रासदी में वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर निगेटिव (-7.3) हो गई थी फिर भी बिहार राज्य की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही है । यह राज्य की सशक्त अर्थव्यवस्था को दर्शाता है ।

कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र--कृषि रोड मैप की उपलब्धि है कि राज्य में खाद्यान्न, ईख, अंडा, मछली, मीट एवं फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । दुग्ध उत्पादन 57.67 मेट्रिक टन से बढ़कर 115 मेट्रिक टन हो गया है । राज्य को पाँच कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है ।

पथ--वर्ष 2005 से अबतक पथ निर्माण विभाग की 18992 किलो मीटर सड़क तथा 6047 पुलों का निर्माण किया गया है । वर्ष 2005 में ग्रामीण पथों की लम्बाई 3112 किलो मीटर थी जो वर्ष 2021 तक 102306 किलो मीटर हो गयी है । हर घर तक पक्की गली-नालियाँ योजना अन्तर्गत 117991 वार्डों के विरुद्ध 117464 वार्डों को आच्छादित किया जा चुका है ।

ऊर्जा--प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 2012-13 के 145 किलोवॉट प्रति घंटा से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 350 किलोवॉट प्रति घंटा हो गयी है ।

पेयजल--सात निश्चत योजना के हर घर नल का जल कार्यक्रम अन्तर्गत नल का जल पा रहे घरों की संख्या 162.78 लाख हो गयी है ।

राज्य की न्याय के साथ विकास की नीति की सफलता राज्य को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की नई ऊँचाई की तरफ ले जा रही है ।

सड़कों का संरक्षण कराना

22. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का प्रतिरक्षण नहीं होने से जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना से निर्मित सड़कों का संरक्षण करने की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग को देने की आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" से निर्मित सड़कों का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण ग्रामीण कार्य विभाग से कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि (i) विभागीय संकल्प संख्या 6737, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में गली-नाली/सम्पर्क पथ की योजना अनुमान्य है ।

(ii) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अनुमान्य योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का प्रावधान नहीं रहने के कारण इसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य नहीं हो पाता था.। ऐसी स्थिति में विभागीय संकल्प संख्या 1172, दिनांक 24 मार्च, 2021 के द्वारा मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों को हस्तांतरित किया जायेगा ।

(iii) सृजित परिसम्पत्तियों के संबंधित प्रशासी विभाग को हस्तांतरण के उपरान्त इसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा एक अलग विषय शीर्ष खोलकर प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान कराया जायेगा ।

(iv) यदि किसी विभाग के पास पूर्व से अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विभागों द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु अलग से बजट शीर्ष खोलकर सृजित एवं हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु बजट प्रावधान कराया जायेगा । ऐसी हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण पर हुये व्यय का लेखा-जोखा संबंधित प्रशासी विभाग के द्वारा अलग से रखा जायेगा ।

(2) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्मित गली-नाली/सम्पर्क पथ के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये संबंधित प्रशासी विभाग को बजट में प्रावधान कर अनुरक्षण एवं रख-रखाव के दायित्व का प्रावधान मार्गदर्शिका में किया गया है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पदस्थापित करना

23. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, 500 है तैनाती के इंतजार में" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत वर्ष अगस्त, 2021 में ही अलग-अलग तिथियों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई समाप्त कर चुके पाँच सौ से अधिक चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के नियमों के तहत पी0 जी0 चिकित्सकों की बंध-पत्र आधारित अनिवार्य विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया लम्बित पड़ी हुई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त चिकित्सकों को कबतक राज्य के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित करना चाहती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 450(1), दिनांक 15 अप्रील, 2017 के अनुसार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उतीर्ण छात्रों से बॉण्ड के तहत तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा लिया जाना है ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा पी0जी0/डिप्लोमा उतीर्ण छात्रों का परीक्षाफल माह दिसम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया ।

तदालोक में 312 पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को विभागीय आदेश संख्या 80(17), दिनांक 23 फरवरी, 2022 द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में आवंटित किया गया है । शेष 138 चिकित्सकों के संस्थान आवंटन प्रक्रियागत है ।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

विचार रखना

24. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "इलाज के लिये एम्बुलेंस में पड़े रहते हैं गंभीर मरीज, कई को 5 घंटे, तो कई को 3 दिन बाद भी बेड नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना आई0 जी0 आई0 एम0 एस0 अस्पताल के इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर के गेट के सामने प्रतिदिन गंभीर मरीजों के लिये दर्जनों एम्बुलेंस कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन बेड नहीं मिल पाने की स्थिति में कइयों को प्राईवेट अस्पताल का रूख करना पड़ता है, तो कई अर्थाभाव में वहीं दम तोड़ देते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त अस्पताल की कमियाँ दूर कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मेंटेन कराना

25. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारियों की 53.21 प्रतिशत की कमी" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवर ऑल 53.21 प्रतिशत का गैप है, जो देश में सबसे अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गैप को कबतक मेंटेन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पोर्टल को शुरू करना

26. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन देने के लिये 'सुविधा' ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा उक्त 'सुविधा' ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था को पिछले एक साल से बंद कर दी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन लेने के लिये 'सुविधा' ऑनलाइन पोर्टल को पुनः शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति करना

27. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक 'पी0एम0सी0एच0 में 78 दवाएँ मिलनी है मुफ्त उपलब्ध केवल 21 ही" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला में स्थित पी0एम0सी0एच0 के ओ0पी0डी0 में 78 दवाएँ मुफ्त में मिलनी है लेकिन अभी मात्र 21 दवाएँ ही मिल रही हैं, जिसके कारण रोगियों को इलाज कराने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार पी0एम0सी0एच0 के ओ0पी0डी0 में 78 प्रकार की स्वीकृत दवाओं की आपूर्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

28. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला में आग लगने और प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों के खलिहानों में आग और प्राकृतिक आपदा से कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत विधानचक के सुशील उपाध्याय, सत्येन्द्र चौबे, महुआरी के ओम सिंह, महेंद्र पासवान, दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत बहेरा गाँव के केशव प्रसाद दुबे, रघुनाथपुर के विक्रम सिंह, विकास सिंह की फसलें क्षतिग्रस्त हुई जिस कारण इनके आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेत-खलिहानों में आग और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति कराना

29. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 1 सितम्बर, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "पिछले सात वर्षों से राज्य स्तर पर नहीं खरीदी गई आयुष दवाएँ" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न ए0पी0एच0सी0 पर 1384 आयुष चिकित्सकों की बहाली की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 के बाद राज्य स्तर पर आयुष दवाओं की खरीद नहीं किये जाने से स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष दवाओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आयुष दवाओं के अभाव के कारण राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात आयुष चिकित्सक मरीजों को एलोपैथी दवाएँ लिखते हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष दवाओं की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

30. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार कृतसंकल्प है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोलर एनर्जी प्लांट लगाने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग अपने घरों को बंद रखते हैं फिर भी सोलर एनर्जी जेनरेट होते रहते हैं जो नष्ट हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिवर्सेबल मीटर लगाकर उत्पादित सोलर एनर्जी को अपने अन्तर्गत लेकर उसका सदुपयोग करने तथा भविष्य में उपभोक्ता की आवश्यकता अनुरूप उसका समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 4 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 86(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550